

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डी.बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 139/2024

रेशमा पत्नी मोहम्मद अली उर्फ बब्लू, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 12, गंगा विहार कॉलोनी, धर्म पार्क, थाना श्याम नगर जयपुर। वर्तमान में ए ब्लॉक, पानी की टंकी के पास, गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती, पी. एस. करणी विहार, जयपुर (राजस्थान)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
- पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर (राजस्थान)।
- पुलिस आयुक्त, जयपुर आयुक्तालय, जयपुर (राज.)।
- पुलिस उपायुक्त, जयपुर दक्षिण, जयपुर (राजस्थान)।
- सलाहकार बोर्ड, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988, राजस्थान, जिसका प्रतिनिधित्व सचिव करेंगे।
- भारत संघ का प्रतिनिधित्व सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 द्वारा किया जाएगा।
- थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन करणी विहार, जयपुर पश्चिम, जयपुर (राज.)।

-----प्रतिवादी

- मोहम्मद अली उर्फ बब्लू पुत्र श्री मोती सैय्यद हुसैन, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 12, गंगा विहार कॉलोनी, धर्म पार्क, थाना श्याम नगर, जयपुर। वर्तमान में ए ब्लॉक, पानी की टंकी के पास, गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती, थाना करणी विहार, जयपुर (राजस्थान) में रह रहा हूं। वर्तमान में हाई सिक्क्योरिटी जेल, अजमेर में।

-----डिटेनु-प्रोफार्मा प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री रिपु दमन सिंह नरूका एडवोकेट के साथ श्री मजहर हुसैन एडवोकेट, श्री जीतेन्द्र सिंह शेखावत एडवोकेट और श्री आशिर गौरी एडवोकेट।
प्रतिवादी संख्या 1 से 4 और 7 के लिए	:	श्री राजेश चौधरी सरकारी अधिवक्ता-सह- अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री गौरव गुप्ता एडवोकेट और श्री अमन अग्रवाल।
प्रतिवादी संख्या 6 के लिए	:	श्री संदीप पाठक एडवोकेट, श्री अक्षत शर्मा एडवोकेट।

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

प्रकाशनीय

04/09/2024

- यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका राजस्थान सरकार (गृह विभाग) द्वारा पारित दिनांक 11.12.2023 के निरोध आदेश का विरोध करती है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के पति को स्वापक

औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे आगे '1988 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 3 के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए निरुद्ध किया गया है।

2. वर्तमान मामले के निर्णय के लिए आवश्यक सर्वोत्कृष्ट तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता बंदी मोहम्मद अली उर्फ बबलू की पत्नी है। उसने हलफनामे में कहा है कि पुलिस उपायुक्त, जयपुर, दक्षिण, जयपुर द्वारा उसके पति को हिरासत में लेने और कार्रवाई शुरू करने के लिए सचिव, गृह (विधि) को दिए गए अनुरोध के आधार पर, 1988 के अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई, जिसके परिणामस्वरूप 11.12.2023 को यह संतुष्टि दर्ज करने पर कि बंदी को मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल होने से रोकने के उद्देश्य से आदेश पारित करना आवश्यक हो गया है, उक्त आदेश पारित किया गया। इस संतुष्टि का आधार बंदी के खिलाफ स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे आगे '1985 का अधिनियम' कहा जाएगा) के प्रावधानों के तहत आठ आपराधिक मामलों का पंजीकरण था।

3. याचिका में यह भी कहा गया है कि केवल पांच मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं, जो विचाराधीन हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में बंदी को दोषी नहीं ठहराया गया है और संबंधित अदालत द्वारा सभी मामलों में उसे जमानत दे दी गई है। नजरबंदी के आदेश से व्यथित होकर, पहले डीबी हैबियस कॉर्पस रिट याचिका संख्या 6/2024 दायर की गई थी, जिसे 06.03.2024 के आदेश द्वारा निपटाया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को सलाहकार बोर्ड द्वारा नजरबंदी के आदेश की पुष्टि होने की स्थिति में उचित उपाय करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इसके बाद, याचिकाकर्ता को पता चला कि 19.02.2024 के आदेश के तहत, नजरबंदी के आदेश को एक वर्ष की अवधि के लिए 10 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यह भी कहा गया है कि बंदी को याचिका में नजरबंदी के संबंध में उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा दस्तावेजों का पूरा सेट प्रदान नहीं किया गया था।

4. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 और प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा दायर जवाब में याचिका में किए गए कथनों को नकार दिया गया है। प्रतिवादियों के अनुसार, याचिकाकर्ता का पति 1985 के अधिनियम के तहत लगातार अपराध करने में शामिल है, जो इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि उसी अधिनियम के तहत उसके खिलाफ आठ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 1985 के अधिनियम के तहत बार-बार अपराध करने के आधार पर संतुष्टि हुई और रिकॉर्ड और प्रासंगिक जानकारी पर विभिन्न सामग्रियों पर विचार करने के बाद, अधिकारी इस संतुष्टि पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता के पति (हिरासत में) को 1985 के अधिनियम के तहत आगे अपराध करने से रोकने के लिए नजरबंदी का आदेश पारित करना आवश्यक हो गया है। यह भी कहा गया है कि न केवल नजरबंदी का आदेश, बल्कि उसके आधार भी नजरबंद को दिए गए थे। नजरबंदी का आदेश सलाहकार बोर्ड के अनुमोदन के लिए भेजा गया था, जिसने अपनी बैठक की प्रतिवादियों के अनुसार, याचिकाकर्ता का पति मादक दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी में शामिल है और बार-बार कार्रवाई और गिरफ्तारी के बावजूद, उसने सुधार के कोई संकेत नहीं दिखाए हैं और लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर खतरा बन गया है और समाज को इस खतरे से बचाने के लिए, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश पारित करना आवश्यक समझा गया।

5. सुनवाई की पिछली तारीख पर, इस न्यायालय ने आधिकारिक प्रतिवादियों के विद्वान वकील को सलाहकार बोर्ड की राय प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसे भी अवलोकन के लिए न्यायालय के समक्ष रखा गया है और उसे रिकॉर्ड पर लिया गया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

6.1 यद्यपि बंदी ने विभिन्न दस्तावेजों की मांग की थी, परंतु याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों के अलावा, उसे कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः, यह 1988 के अधिनियम में निहित भौतिक प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन है और इसी आधार पर, बंदी आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

6.2 हालांकि बंदी के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं, फिर भी उसे सभी मामलों में जमानत दे दी गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि मामले निराधार हैं और बंदी को पुलिस अधिकारियों द्वारा बार-बार झूठा फंसाया जा रहा है। एक बार बंदी को उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में जमानत दे दी गई, तो 1988 के अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त हिरासत की शक्ति का आह्वान नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे आवश्यक निहितार्थ द्वारा बाहर रखा गया है।

6.3 बंदी के मामले में हिरासत का आदेश पारित किए जाने से पहले ही, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 [जैसा कि लागू था] की धारा 110 के तहत कार्यवाही की गई, (जिसे आगे 'सीआरपीसी' कहा जाएगा) तैयार की गई और 13.10.2023 को एक आदेश पारित किया गया जिसमें बंदी को अच्छे आचरण और शांति के लिए बांड और जमानत जमा करने की आवश्यकता थी। एक बार आदेश पारित हो जाने के बाद, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के लिए 1988 के अधिनियम की धारा 3 के तहत शक्ति का उपयोग करने का कोई अवसर नहीं था, जब तक कि यह न पाया जाए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने अच्छे आचरण को बनाए रखने के लिए बांड की शर्तों का उल्लंघन किया है।

6.4 ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं। केवल पांच मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं और शेष तीन मामलों में जांच लंबित है। इसलिए, इसे हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रकृति का मामला नहीं कहा जा सकता है, ताकि 1988 के अधिनियम की धारा 3 के तहत निवारक निरोध के चरम प्रावधानों को लागू किया जा सके, जिसका प्रभाव किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के और यहां तक कि कई आपराधिक मामलों में अपराध करने के आरोप के सबूत के बिना हिरासत में रखना है, जो अभी भी विभिन्न चरणों में लंबित हैं।

प्रस्तुतियों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य **(1984) 3 एससीसी 14**; अशोक कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य **(1982) 2 एससीसी 403**; सुशांत कुमार बनिक बनाम त्रिपुरा राज्य और अन्य, एआईआर **2022 एससी 4715**; श्रीमती अज़रा फातिमा बनाम भारत संघ और अन्य **(1991) 1 एससीसी 76**; के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा। बुरहान मुश्ताक बनाम जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश (डब्ल्यूपी (सीआरएल) संख्या **287/2023, 22.03.2024** को तय किया गया) और मुख्तार अहमद डार बनाम जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश (डब्ल्यूपी (सीआरएल) संख्या **120/2023, 26.12.2023** को तय किया गया) के मामलों में श्रीनगर में

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के फैसले; शाहिद खान @ छोटे प्रधान बनाम भारत संघ और अन्य (डब्ल्यूपी (सीआरएल) संख्या **224/2023, 15.04.2024** को तय किया गया) के मामले में दिल्ली के उच्च न्यायालय का निर्णय।

7. प्रतिपक्ष, प्रतिवादी-राज्य के साथ-साथ भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि निवारक निरोध का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई संतुष्टि पर पहुंचने और 1988 के अधिनियम में निहित विभिन्न प्रावधानों के उचित पालन और अनुपालन के बाद वैध रूप से पारित किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सक्षम पुलिस प्राधिकारी ने निरोध के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए सरकार को एक अनुरोध भेजा क्योंकि यह पाया गया कि बंदी 1985 के अधिनियम के तहत अपराधों के कमीशन में बार-बार शामिल था और उसके खिलाफ आठ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट और सामग्री प्राप्त होने पर, सक्षम निरोध प्राधिकारी ने अपना दिमाग लगाया, संबंधित कारकों और उसके सामने रखी गई सामग्री पर विचार किया, जिसमें आपराधिक मामलों में बंदी को जमानत दिए जाने के तथ्य के साथ-साथ 13.10.2023 को कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के बारे में तथ्य भी शामिल था। उपरोक्त सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद, हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता के पति यानी बंदी को 1985 के अधिनियम के तहत अपराध करने से रोकने के उद्देश्य से हिरासत में लेना आवश्यक हो गया है। राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश को कानून के तहत सलाहकार बोर्ड के विचार और राय के लिए भेजा गया था। सलाहकार बोर्ड ने बंदी को सुनवाई का अवसर दिया और उसे सुनने के बाद और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद, सलाहकार बोर्ड ने अपनी राय दर्ज की कि हिरासत का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त आधार थे। सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त होने के बाद, राज्य सरकार ने कानून के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए बंदी को हिरासत में लेने का आदेश पारित किया। यह आगे तर्क दिया गया है कि 1988 के अधिनियम के प्रावधानों में हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को हिरासत के आदेश और हिरासत के आधार के अलावा किसी अन्य दस्तावेज की आपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रतिवादियों के विद्वान वकीलों का यह भी तर्क है कि यद्यपि बंदी को विभिन्न आपराधिक मामलों में मुख्यतः इस कारण जमानत दी गई थी कि उन मामलों में शामिल मात्रा व्यावसायिक मात्रा से कम थी, फिर भी इससे बंदी के मामले में कोई सुधार नहीं होता, और न ही सक्षम निरोधक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र का हनन होता है कि वह जाँच करे और उचित स्थिति में निरोध का आदेश पारित करे। प्रतिवादियों के विद्वान वकीलों के अनुसार, 1988 के अधिनियम की योजना में ऐसा कोई बंधन नहीं है और अन्यथा, निर्णयों की श्रृंखला में यह बात पूरी तरह से स्थापित है कि केवल इसलिए कि बंदी को जमानत दी गई थी, निरोध के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

9. हिरासत के आदेश पारित करने से पहले सीआरपीसी की धारा 110 के तहत आदेश पारित करने के संबंध में प्रस्तुत जवाब में, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 110 अलग क्षेत्र में काम करती है और यह विशेष अधिनियम, यानी 1988 के अधिनियम के तहत हिरासत की शक्तियों का प्रयोग करने के रास्ते में नहीं आती है, जिसे उन लोगों से निपटने के

लिए अधिनियमित किया गया है, जो 1985 के अधिनियम के तहत अपराध करने में शामिल हैं और ऐसे अपराधों के कमीशन को रोकने के लिए 1988 के अधिनियम के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

10. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने अंत में प्रस्तुत किया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ दर्ज सभी आठ आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं, जो हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है।

11. प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा की गई सामान्य दलीलों के अलावा, प्रतिवादी-भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने एक और मुद्दा उठाया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के रूप में प्रस्तुत यह याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि यह अवैध हिरासत का मामला नहीं है, बल्कि 1988 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिरासत प्राधिकारी द्वारा पारित हिरासत आदेश का मामला है।

12. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है तथा सलाहकार बोर्ड की राय भी हमारे अवलोकनार्थ हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है।

13. राज्य सरकार द्वारा पारित हिरासत के आदेश से पता चलता है कि पुलिस उपायुक्त, जयपुर (दक्षिण) ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ राज्य सरकार को एक शिकायत भेजी थी जिसमें अनुरोध किया गया था कि वह 1988 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिरासत का आदेश पारित करे। शिकायत में कहा गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ 1985 के अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोप में आठ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और उन सभी मामलों में सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पहले ही दायर किए जा चुके हैं। शिकायत में आगे कहा गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ 1985 के अधिनियम के तहत कथित अपराध करने के लिए 2019 से आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं और लगभग सभी मामलों में मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की बिक्री से एकत्र की गई नकदी भी जब्त की गई है। बंदी के विरुद्ध वर्ष 2023 में तीन, वर्ष 2022 में एक, वर्ष 2021 में एक, वर्ष 2020 में दो और वर्ष 2019 में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है तथा 8,63,710/- रुपये की नकदी भी जब्त की गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि बंदी स्वयं नशे का आदी है और लंबे समय से लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त है, जिससे समाज के स्वास्थ्य और कल्याण पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही यह अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है। यह भी कहा गया है कि यद्यपि बंदी को ऐसी गतिविधियों से दूर रखने का प्रयास किया गया, फिर भी वह लगातार ऐसे अपराधों में संलिप्त पाया गया है।

14. पुलिस उपायुक्त, जयपुर (दक्षिण) से उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने पर, राज्य सरकार ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जाँच की और 2019 से 2023 तक बंदी के विरुद्ध दर्ज विभिन्न आपराधिक मामलों का विवरण दर्ज किया। विवरण में बंदी से कथित रूप से ज़ब्त की गई मादक दवाओं और मनोविकार नाशक पदार्थों की मात्रा और प्रकृति के साथ-साथ उससे ज़ब्त की गई नकदी राशि भी शामिल थी। बंदी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सामग्री में बंदी से 'गांजा' और 'स्मैक' दोनों की ज़बती दिखाई गई। बंदी प्राधिकारी ने यह भी ध्यान में रखा कि बंदी के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 110 के तहत कार्यवाही भी की गई थी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 13.10.2023 को एक आदेश भी

पारित किया गया था। राज्य सरकार अपने समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त सामग्री पर विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बंदी को 1985 के अधिनियम के तहत अपराध करने से रोकने के लिए, 1988 के अधिनियम की धारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरोध का आदेश पारित करना आवश्यक हो गया है।

15. जैसा कि उत्तर में कहा गया है और याचिकाकर्ता द्वारा अभिलेख में भी प्रस्तुत किया गया है, आदेश के साथ, हिरासत के आधार भी उसी तिथि के ज्ञापन द्वारा बंदी को सूचित किए गए थे। याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में, हिरासत के आधारों के साथ हिरासत के आदेश की सूचना बंदी को देने से संबंधित प्रावधानों के पालन न करने के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया है। इसलिए, हमारा मानना है कि जहाँ तक हिरासत के आधारों के साथ हिरासत के आदेश की सूचना का संबंध है, 1988 के अधिनियम की धारा 3(3) में वर्णित कानून की आवश्यकता का पालन किया गया है।

16. 1988 के अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान है कि समुचित सरकार को कानून के तहत गठित सलाहकार बोर्ड को संदर्भ भेजना होगा। 1988 के अधिनियम की धारा 9(एफ) में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक मामले में जहाँ सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि उसकी राय में, किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त कारण हैं, समुचित सरकार हिरासत आदेश की पुष्टि कर सकती है और संबंधित व्यक्ति की हिरासत को उस अवधि के लिए जारी रख सकती है, जितनी वह उचित समझे।

17. 1988 के अधिनियम की धारा 11 में निरोध की अधिकतम अवधि का प्रावधान है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे निरोध आदेश के अनुसरण में, जिस पर 1988 के अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और जिसकी पुष्टि 1988 के अधिनियम की धारा 9 के खंड (च) के अंतर्गत की गई है, निरोध की तिथि से एक वर्ष तक की अधिकतम अवधि निरोध की जाएगी। इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि जिन मामलों में निरोध 1988 के अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत है, वहाँ निरोध की तिथि से दो वर्ष तक की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

18. 1988 के अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान है कि यदि सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट हो कि उसे मादक दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल होने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो निरोध का आदेश पारित किया जा सकता है।

19. इस स्थापित कानूनी प्रस्ताव से कोई विवाद नहीं हो सकता कि निरोध कानूनों की सख्त व्याख्या आवश्यक है और निरोध का कोई भी आदेश, जो निरोध कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, कायम नहीं रहेगा क्योंकि यह निरुद्ध व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर, हमें ऐसा नहीं लगता कि 1988 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है।

20. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह निवेदन कि बंदी को याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों के अलावा कोई अन्य दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, इस तथ्य की स्वीकृति है कि नजरबंदी का आदेश और नजरबंदी के आधार दोनों बंदी को दिए गए थे। इससे भी अधिक, 1988 के अधिनियम के प्रावधान नजरबंदी प्राधिकारी को बंदी को कोई अन्य आदेश संप्रेषित करने के लिए अनिवार्य नहीं करते हैं। यह

तर्क कि सलाहकार बोर्ड की राय की प्रति बंदी को नहीं दी गई है, हमारी राय में, नजरबंदी के आदेश को निष्प्रभावी नहीं करेगा क्योंकि 1988 के अधिनियम के प्रावधानों में कहीं भी यह आवश्यक नहीं है कि सलाहकार बोर्ड द्वारा सरकार को राय दिए जाने के बाद सरकार बंदी को सलाहकार बोर्ड की राय की एक प्रति देने के लिए बाध्य है। यह अलग बात हो सकती है कि मांग के बाद भी, सलाहकार बोर्ड की राय की प्रति बंदी को नहीं दी गई है। लेकिन, बिना किसी अतिरिक्त बात के, यह अपने आप में 1988 के अधिनियम के किसी भी अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, दस्तावेज़ उपलब्ध न कराने के संबंध में याचिका में दिए गए दावे अस्पष्ट हैं। याचिका में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि कौन सा दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन बंदी को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए, बंदी को हिरासत में रखने के आदेश को चुनौती देने का पहला आधार हमें स्वीकार्य नहीं है और इसे आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

21. दूसरा निवेदन, जो याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि एक बार आपराधिक मामलों में बंदी को जमानत दे दी जाए तो 1988 के अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त निरोध की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस निवेदन के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने विजय नारायण सिंह (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अत्यधिक सहारा लिया है। उस मामले में याचिकाकर्ता, जो एक छात्र था, फिरौती की मांग पूरी न होने पर दो व्यक्तियों की हत्या के एक मामले में संलिप्त था। इस मामले में याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया गया और बाद में 09.08.1983 के आदेश के तहत उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया। हालाँकि, उसे जमानत पर रिहा किए जाने से पहले ही 16.08.1983 को निरोध का आदेश पारित कर दिया गया। पीड़ित व्यक्ति ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की, जो अंततः खारिज कर दी गई, हालाँकि यह छूट दी गई थी कि यदि याचिकाकर्ता को निरोध आदेश की प्रति प्रदान की जाती है और उसे जेल में नज़रबंद रखा जाता है, तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने के लिए नई याचिका दायर कर सकता है। हालाँकि, उच्च न्यायालय जाने के बजाय, याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि की निम्नलिखित रूप से जाँच की:

“32. वर्तमान मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को एक असामाजिक तत्व मानने के लिए तीन घटनाओं का हवाला दिया है। वे हैं- (i) कि 15 अप्रैल, 1975 को याचिकाकर्ता अपने साथियों के साथ भागलपुर शहर के एक कपड़ा व्यापारी की दुकान पर बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल से लैस होकर गया था और बंदूक की नोक पर जबरन चंदा मांगा था और (ii) कि 17/18 जून, 1982 को याचिकाकर्ता एक सिनेमा हॉल से लौट रही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार करते पाया गया था। तीसरा आधार सत्र न्यायालय में याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित आपराधिक मामला है। पहली घटना वर्ष 1975 की है। यह नहीं बताया गया है कि उस आरोप के आधार पर दायर आपराधिक मामला कैसे समाप्त हुआ। अगली घटना वर्ष 1982 से संबंधित है। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने यह नहीं बताया कि उस संबंध में दायर आपराधिक मामला कैसे समाप्त हुआ। यदि दोनों ही मामले याचिकाकर्ता के पक्ष में समाप्त हुए हैं और उसे स्पष्ट रूप से निर्दोष पाया गया है, तो वे निश्चित रूप से आदतन किए गए कार्य या चूक नहीं माने जा सकते। याचिकाकर्ता द्वारा की गई। इसके

अलावा, उक्त दोनों घटनाएँ बिल्कुल अलग-अलग प्रकार की हैं। जबकि पहली घटना अधिनियम की धारा 2(डी) के उप-खंड (i) के अंतर्गत आ सकती है, दूसरी घटना इसके उप-खंड (iv) के अंतर्गत आती है। यदि वे सत्य भी हैं, तो एक ही प्रकार के कृत्यों या चूक की पुनरावृत्ति नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने मामले के उपरोक्त पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया है। तीसरा आधार, जो लंबित सत्र मामले पर आधारित है, निस्संदेह धारा 2(डी) के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट कृत्यों या चूक की प्रकृति का है, लेकिन पहले आधार, जो इस उप-खंड के अंतर्गत आता है, और इस आधार के बीच का अंतराल लगभग आठ वर्ष का है और इसलिए, याचिकाकर्ता को धारा 2(डी) के उप-खंड (i) के अंतर्गत आने वाले प्रकार का आदतन अपराधी नहीं बनाया जा सकता है।

22. उस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में, विशेष रूप से उस मामले में लागू कानून की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या उन परिस्थितियों में संबंधित व्यक्ति को आदतन अपराधी के रूप में चिह्नित किया जा सकता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

"32. लेकिन अब विचारणीय बिंदु यह है कि क्या आरोप-पत्र दाखिल करना याचिकाकर्ता को अधिनियम के अंतर्गत लाने के लिए पर्याप्त है। न्यायालय को आपराधिक मुकदमे में शामिल घटना की वीभत्सता से प्रभावित हुए बिना मामले की जाँच करनी चाहिए।"

23. उपर्युक्त मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर, जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि कथित जघन्य प्रकृति के एक विशिष्ट आपराधिक मामले को आधार बनाया गया था और अन्य पृष्ठभूमि से आदतन अपराधी का मामला नहीं बनता, यह निर्णय दिया गया कि निवारक निरोध कानून का उपयोग केवल किसी आपराधिक मुकदमे में शामिल अभियुक्त के पर कतरने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को निरोध में रखना नहीं है, जब सामान्य आपराधिक कानून के तहत जमानत आदेश जारी करने का विरोध करना संभव न हो। ऐसा दर्ज करते समय भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसा कोई उपाय तब तक उपलब्ध नहीं हो सकता जब तक कि उपलब्ध सामग्री ऐसी न हो जो ऐसी निरोध को अधिकृत करने वाले कानूनी प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा करती हो। उपरोक्त निर्णय सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाले कानून के किसी ऐसे प्रस्ताव को प्रतिपादित नहीं करता है कि सभी मामलों में जहाँ किसी अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, निवारक निरोध के प्रावधानों को लागू नहीं किया जाना चाहिए और निवारक निरोध का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं :

"32. यह सर्वविदित है कि निवारक निरोध का कानून एक कठोर कानून है और इसलिए इसकी व्याख्या कठोरता से की जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक खतरे में न पड़े जब तक कि उसका मामला संबंधित कानून के दायरे में न आता हो। निवारक निरोध के कानून का इस्तेमाल केवल किसी आपराधिक मुकदमे में शामिल अभियुक्त के पर कतरने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस समय हिरासत में रखना नहीं है जब सामान्य आपराधिक कानून के तहत जमानत के आदेश जारी होने का विरोध करना संभव न हो, जब तक कि उपलब्ध सामग्री ऐसी न हो जो ऐसी हिरासत

को अधिकृत करने वाले कानूनी प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा करती हो। जब किसी व्यक्ति को सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाता है, तो निवारक निरोध के आदेश की वैधता की जाँच करते समय बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए, जो उसी आरोप पर आधारित है जिस पर आपराधिक न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है।”

24. इसलिए, उपर्युक्त निर्णय बंदी के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है, क्योंकि वर्तमान में बंदी के विरुद्ध अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत कथित अपराधों से संबंधित आठ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

25. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस तर्क के समर्थन में सुशांत कुमार बनिक (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भारी भरोसा जताया है कि जहां एक बार आरोपी को जमानत दे दी जाती है, वहां नजरबंदी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त मामले में, तथ्यों के आधार पर, यह पाया गया कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी इस तथ्य से अनभिज्ञ रहा कि हिरासत के आदेश पारित करने के उद्देश्य से हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दोनों आपराधिक मामलों में, बंदी को विशेष न्यायालय द्वारा रिहा करने का आदेश दिया गया था। इस तथ्यात्मक आधार पर, यह देखा गया कि आपराधिक मामलों में जमानत पर रिहा किए जा रहे बंदी के एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण तथ्य को संबंधित प्राधिकारी द्वारा निवारक नजरबंदी का उचित आदेश पारित करने के प्रस्ताव को अग्रेषित करते समय दबा दिया गया था या हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाया गया था। इसके अलावा, उस मामले की एक और खास बात यह थी कि विशेष अदालत ने 1985 के अधिनियम की धारा 37 की कठोरता के बावजूद जमानत दे दी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि जिन मामलों में 1985 के अधिनियम की धारा 37 लागू होती है, उनमें जमानत देने से यह पता चलता है कि अगर किसी अभियुक्त को 1985 के अधिनियम की धारा 37 की कठोरता के बावजूद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था, तो यह इस तथ्य का सूचक है कि संबंधित न्यायालय को अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं मिला होगा और अगर यह तथ्य हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया होता, तो यह हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के मन को किसी न किसी तरह से इस सवाल पर प्रभावित करता कि हिरासत का आदेश दिया जाए या नहीं। उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, 1985 के अधिनियम की धारा 37 में निहित प्रावधानों के प्रकाश में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

“22. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस मामले में, यहां अपीलकर्ता को निवारक रूप से हिरासत में लेने के उद्देश्य से हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दोनों मामलों में, अपीलकर्ता को पहले ही संबंधित विशेष न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। निस्संदेह, हम हिरासत के आदेश को संसाधित करने का अनुरोध करते हुए पश्चिम त्रिपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में इस तथ्य का कोई संदर्भ नहीं पाते हैं। मामले के इस पहलू पर अधिक जोर देने का कारण यह तथ्य है कि अपीलकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, विशेष न्यायालय, त्रिपुरा ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 की कठोरता के

बावजूद अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित समझा। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 इस प्रकार है:

“धारा 37. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना।-(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित किसी बात के होते हुए भी (1974 का 2)-

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;

(ख) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27 क के अधीन अपराधों के लिए तथा वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि—

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत को यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाएं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या जमानत देने पर वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अतिरिक्त हैं।

23. उपर्युक्त प्रावधान को सीधे पढ़ने से पता चलता है कि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश तभी दिया जा सकता है जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यदि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 की कठोरता के बावजूद अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था, तो यह इस बात का संकेत है कि संबंधित न्यायालय को उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं मिला होगा। यदि यह तथ्य हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के संज्ञान में लाया गया होता, तो यह हिरासत में लेने का आदेश देने या न देने के सवाल पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के मन को किसी न किसी तरह प्रभावित करता। राज्य ने अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने वाले विशेष न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेशों को चुनौती देने के बारे में कभी नहीं सोचा।

26. उस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, आशा देवी बनाम गुजरात सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं अन्य, **1979** सीआरएल एलजे **203** और इसके निज़ामुद्दीन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, **(1975) 3** एससीसी **395** के मामलों में प्रतिपादित कानून का सहारा लिया गया ताकि यह प्रतिपादित किया जा सके कि यदि निरोध आदेश जारी किया जाए या नहीं, इस प्रश्न पर निरोधक प्राधिकारी के मन को किसी न किसी तरह प्रभावित करने वाले भौतिक या महत्वपूर्ण तथ्य निरोधक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाते या उन पर विचार नहीं किया जाता, तो यह उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि को दूषित करेगा और निरोध आदेश को अवैध बना देगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“26. उपरोक्त निर्णयों से यह उभर कर आता है कि अपेक्षित व्यक्तिपरक संतुष्टि, जिसका गठन निरोध आदेश पारित करने के लिए एक पूर्व शर्त है, तब दूषित हो

जाएगी यदि सामग्री या महत्वपूर्ण तथ्य जो मुद्दे पर असर डालते हैं और किसी न किसी तरह से निरोध प्राधिकारी की संतुष्टि को प्रभावित करते हैं और उसके मन को प्रभावित करते हैं, प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा या तो रोक दिए जाते हैं या दबा दिए जाते हैं या निरोध आदेश जारी करने से पहले निरोध प्राधिकारी द्वारा नजरअंदाज कर दिए जाते हैं और उन पर विचार नहीं किया जाता है।

27. हमारे दिमाग में यह स्पष्ट है कि इस मामले में, जब हिरासत प्राधिकारी ने हिरासत आदेश पारित किया था, तो यह महत्वपूर्ण तथ्य, अर्थात्, अपीलकर्ता बंदी को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 की कठोरता के बावजूद विशेष न्यायालय, त्रिपुरा द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था, ध्यान में नहीं लाया गया था और दूसरी ओर, इस तथ्य को रोक दिया गया था और हिरासत प्राधिकारी को यह समझने के लिए दिया गया था कि उन आपराधिक मामलों का परीक्षण लंबित था।

27. अतः, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त मामले में, महत्वपूर्ण/महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना ही विवाद का कारण माना गया था। इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया उपरोक्त दृष्टिकोण, हमारे समक्ष प्रस्तुत इस तर्क का समर्थन नहीं करता है कि जब भी जमानत दी जाती है, तो निरोध कानूनों के तहत निवारक निरोध का आदेश पारित करने की शक्ति का सहारा नहीं लिया जा सकता।

28. हरियाणा वित्तीय निगम एवं अन्य बनाम जगदम्बा ऑयल मिल्स एवं अन्य **(2002) 3 एससीसी 496** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती कानून की व्याख्या इस प्रकार की गई है:

"19. न्यायालयों को इस बात पर चर्चा किए बिना किसी निर्णय पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि जिस निर्णय पर भरोसा किया जा रहा है, उसकी तथ्यात्मक स्थिति और तथ्यात्मक स्थिति में क्या समानता है। न्यायालयों की टिप्पणियों को यूक्लिड के प्रमेयों या कानून के प्रावधानों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इन टिप्पणियों को उसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे प्रकट होती हैं। न्यायालयों के निर्णयों को कानून के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। किसी कानून के शब्दों, वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन चर्चा का उद्देश्य व्याख्या करना है, परिभाषित करना नहीं। न्यायाधीश कानूनों की व्याख्या करते हैं, वे निर्णयों की व्याख्या नहीं करते। वे कानूनों के शब्दों की व्याख्या करते हैं, उनके शब्दों की व्याख्या कानून के रूप में नहीं की जानी चाहिए। लंदन ग्रेविंग डॉक कंपनी लिमिटेड बनाम हॉर्टन 1951 एसी 737 (पृष्ठ 761 पर) में लॉर्ड मैकडरमोट ने कहा: (ऑल ईआर पृष्ठ 14 सी-डी) "निःसंदेह, केवल मामलों का निपटारा करके मामले का निपटारा नहीं किया जा सकता। इप्सिसिमा विल्स, जे. के वर्बा को ऐसे पेश किया गया मानो वे संसद के किसी अधिनियम का हिस्सा हों और व्याख्या के नियमों को उनके अनुरूप लागू किया गया हो। इसका मतलब यह नहीं है कि उस अत्यंत प्रतिष्ठित न्यायाधीश द्वारा वास्तव में प्रयुक्त भाषा को दिए जाने वाले महत्व को कम किया जाए।"

20. होम ऑफिस बनाम डोरसेट यॉट कंपनी (1970) 2 ऑल ईआर 294 में लॉर्ड रीड ने कहा (ऑल ईआर पृष्ठ 297 जी-एच पर), "लॉर्ड एटकिन के भाषण को... किसी वैधानिक परिभाषा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। नई परिस्थितियों में इसे और स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी।" मेगारी, जे. ने (1971) 1 डब्ल्यूएलआर 1062 में टिप्पणी की: "निश्चित रूप से, रसेल एल.जे. के किसी भी आरक्षित निर्णय को भी

संसद के अधिनियम के रूप में नहीं समझना चाहिए।" और, हेरिंगटन बनाम ब्रिटिश रेलवे बोर्ड (1972) 2 डब्ल्यूएलआर 537 में लॉर्ड मॉरिस ने कहा: (ऑल ईआर पृष्ठ 761 सी)

"किसी भाषण या निर्णय के शब्दों को विधायी अधिनियम के शब्दों के रूप में मानना हमेशा जोखिम भरा होता है, और यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक कथन किसी विशेष मामले के तथ्यों के संदर्भ में दिए जाते हैं।"

21. परिस्थितिजन्य लचीलापन, एक अतिरिक्त या भिन्न तथ्य दो मामलों के निष्कर्षों में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। किसी निर्णय पर आँख मूंदकर भरोसा करके मामलों का निपटारा करना उचित नहीं है।

22. मिसालों को लागू करने के मामले में लॉर्ड डेनिंग के निम्नलिखित शब्द लोकस क्लासिकस बन गए हैं:

"प्रत्येक मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है और एक मामले और दूसरे के बीच घनिष्ठ समानता पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक भी महत्वपूर्ण विवरण पूरे पहलू को बदल सकता है। ऐसे मामलों का फैसला करते समय, किसी को एक मामले के रंग को दूसरे के रंग से मिलाकर मामलों का फैसला करने के प्रलोभन से बचना चाहिए (जैसा कि कार्डोजो ने कहा है)। इसलिए, यह तय करने के लिए कि कोई मामला रेखा के किस तरफ आता है, दूसरे मामले से व्यापक समानता बिल्कुल भी निर्णायक नहीं है।

* * *

"मिसाल का पालन केवल वहीं तक किया जाना चाहिए जहां तक वह न्याय के मार्ग को चिह्नित करता है, लेकिन आपको मृत लकड़ी को काटना होगा और किनारे की शाखाओं को छांटना होगा अन्यथा आप खुद को झाड़ियों और शाखाओं में खोया हुआ पाएंगे। मेरी दलील है कि न्याय के मार्ग को उन बाधाओं से मुक्त रखें जो इसे बाधित कर सकती हैं।"

29. हाल ही में सिकंदराबाद क्लब आदि बनाम सी.आई.टी.-वी आदि, एआईआरऑनलाइन **2023 एससी 702** के मामले में दिए गए एक फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के इस स्थापित सिद्धांत को दोहराया कि किसी निर्णय का केवल रेशियो डिसाइडेंडी ही मिसाल के तौर पर बाध्यकारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"13. कानून की यह स्थापित स्थिति है कि किसी निर्णय का केवल अनुपात निर्णायक एक मिसाल के रूप में बाध्यकारी है। बी। शमा राव बनाम केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, एआईआर 1967 एससी 1480 में, यह देखा गया है कि एक निर्णय अपने निष्कर्ष के कारण नहीं बल्कि इसके अनुपात और उसमें निर्धारित सिद्धांत के संबंध में बाध्यकारी है। इस संदर्भ में, क्विन बनाम लेथम, 1901 एसी 495 (एचएल) का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें यह देखा गया था कि प्रत्येक निर्णय को उन विशेष तथ्यों पर लागू होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जो साबित हुए हैं, या साबित होने की उम्मीद है, क्योंकि अभिव्यक्तियों की व्यापकता जो वहां पाई जा सकती है, पूरे कानून की व्याख्या करने के लिए नहीं है, बल्कि उस मामले के विशेष तथ्यों द्वारा शासित और योग्य है जिसमें ऐसे भाव पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, एक मामला केवल एक प्राधिकार है

14. दलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1979) 3 एससीसी 745: (एआईआर 1979 एससी 1384) में न्यायमूर्ति ए.पी. सेन के असहमतिपूर्ण निर्णय पर भी भरोसा किया जा सकता है, जिसमें माननीय न्यायाधीश ने कहा था कि किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सजा के प्रश्न पर दिए गए निर्णय को कभी भी बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जा सकता, संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ में

"घोषित विधि" तो बिल्कुल नहीं, ताकि भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों को बाध्य किया जा सके। मिसालों के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक निर्णय में तीन मूल तत्व होते हैं:

- (i) प्रत्यक्ष और अनुमानात्मक, भौतिक तथ्यों के निष्कर्ष । तथ्य का अनुमानात्मक निष्कर्ष वह निष्कर्ष है जो न्यायाधीश प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तथ्यों से निकालता है;
- (ii) तथ्यों द्वारा प्रकट की गई विधिक समस्याओं पर लागू विधि के सिद्धांतों का कथन; और
- (iii) उपरोक्त (i) और (ii) के संयुक्त प्रभाव के आधार पर निर्णय।

पक्षकारों और उनके निजी हितों के लिए, घटक (iii) निर्णय का एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि यह कार्रवाई की विषय-वस्तु के संबंध में उनके अधिकारों और दायित्वों का अंततः निर्धारण करता है। यह निर्णय ही है जो पक्षों को विवाद को फिर से खोलने से रोकता है। हालाँकि, मिसाल के सिद्धांत के उद्देश्य के लिए, घटक (ii) निर्णय का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह रेशियो डिसाइडेंडी है । एक न्यायाधीश द्वारा निर्णय देते समय कही गई हर बात मिसाल नहीं बनती। एक न्यायाधीश के निर्णय में एक पक्षकार को बाध्य करने वाली एकमात्र चीज़ वह सिद्धांत है जिस पर मामले का निर्णय किया जाता है और इसी कारण से एक निर्णय का विश्लेषण करना और उससे रेशियो डिसाइडेंडी को अलग करना महत्वपूर्ण है ।

15. क्वालकास्ट (वॉल्वरहैम्प्टन) लिमिटेड बनाम हेन्स, 1959 एसी 743 के प्रमुख मामले में, यह प्रतिपादित किया गया था कि रेशियो डिसाइडेंडी को विधि के एक कथन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो प्राप्त तथ्यों द्वारा उत्पन्न कानूनी समस्याओं पर लागू होता है, जिन पर निर्णय आधारित होता है। निर्णय के अन्य दो तत्व पूर्वोदाहरण नहीं हैं। कोई निर्णय बाध्यकारी नहीं होता (सिवाय इसके कि स्वयं पक्षकारों पर प्रत्यक्ष रूप से बाध्यकारी हो), न ही तथ्यों के निष्कर्ष बाध्यकारी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जहाँ किसी पूर्ववर्ती मामले के प्रत्यक्ष तथ्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित मामले के समान प्रतीत होते हैं, वहाँ भी न्यायाधीश पूर्ववर्ती मामले में निकाले गए निष्कर्ष के समान निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य नहीं है।

16. किसी मामले में निर्णय को निर्देशित करने वाले विधिक सिद्धांत, मामले के पक्षकारों को आबद्ध करने वाले निर्णय के अलावा, किसी परवर्ती मामले के लिए बाध्यकारी मिसाल का आधार होते हैं। इस प्रकार, निर्णय में निहित सिद्धांत किसी परवर्ती मामले के लिए एक मिसाल के रूप में बाध्यकारी होगा। इसलिए, किसी बाद के मामले में निर्णय लागू करते समय, उस पर विचार करने वाले न्यायालय को पूर्व निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत का सावधानीपूर्वक निर्धारण करना होगा। किसी मामले में निर्णय, मामले के तथ्यों और संबंधित तथा निर्णीत विधि के प्रश्न से प्रभावित होता है। हालाँकि, ऐसा निर्णय जो अभिव्यक्त न हो और न ही किसी तर्क पर आधारित हो और न ही किसी मुद्दे पर विचार के आधार पर आगे बढ़ता हो, उसे घोषित विधि नहीं माना जा सकता, ताकि उसका बाध्यकारी प्रभाव हो, जैसा कि अनुच्छेद 141 के अंतर्गत परिकल्पित है, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (1991) 4 एससीसी 139 में वर्णित है। (एआईआरऑनलाइन 1991 एससी 57) संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। इसलिए, भारत की सभी अदालतें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। यह सिद्धांत न्यायिक अनुशासन का एक पहलू है।

17. यदि कोई निर्णय, निर्णय या फैसले में वर्णित कारणों के आधार पर लिया जाता है, तो केवल रेशियो डिसाइडेंडी ही बाध्यकारी होता है। किसी निर्णय में निहित कारणों और सिद्धांतों का अनुपात या आधार, किसी दिए गए मामले में दी गई अंतिम राहत या अपनाए गए निपटान के तरीके से भिन्न होता है। रेशियो डिसाइडेंडी ही एक मिसाल कायम करता है, न कि फैसले में अंतिम आदेश, देखें संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद; (2007) 3 एससीसी 720: (एआईआर 2007 एससी 950)। इसलिए, केवल मामले के तथ्यों पर लागू होने वाले निर्णय को बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जा सकता।

18. xxxxxx

19. इसलिए, बाध्यकारी वह सिद्धांत है जो किसी निर्णय में अंतर्निहित होता है, जिसे उस मामले से संबंधित प्रश्न(प्रश्नों) के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिससे निर्णय प्रभावित होता है। किसी परवर्ती मामले में, किसी निर्णय पर उस प्रस्ताव के समर्थन में भरोसा नहीं किया जा सकता जिस पर उसने निर्णय नहीं दिया है। इसलिए, जिस संदर्भ या प्रश्न पर विचार करते हुए निर्णय दिया गया है, वह महत्वपूर्ण हो जाता है।

20. Xxxxx

21. किसी निर्णय को समझने के संदर्भ में, यह सर्वविदित है कि निर्णय में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या किसी कानून के शब्दों के रूप में नहीं की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्णय में प्रयुक्त शब्दों को संदर्भ के अनुसार ही प्रस्तुत और समझा जाना चाहिए, न कि उन्हें शाब्दिक रूप से लिया जाना चाहिए। इसके अलावा, कोई निर्णय इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसमें निहित अर्थ क्या है या न्यायाधीशों के किसी कल्पित इरादे को मानकर उससे किसी ऐसे कानूनी प्रस्ताव का अनुमान लगाया जा सकता है जिसे न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में विशिष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, निर्णय उस बात का प्रमाण है जो विशिष्ट रूप से तय की जाती है, न कि उस बात का जो उससे तार्किक रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

30. इसलिए, बार में उद्धृत विजय नारायण सिंह (सुप्रा) और सुशांत कुमार बनिक (सुप्रा) के मामलों में दो फैसले याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील को आगे नहीं बढ़ाते हैं कि एक बार आपराधिक मामले में जमानत मिल जाने के बाद निवारक हिरासत का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। मुख्तार अहमद डार (सुप्रा) और शाहिद खान उर्फ छोटे प्रधान (सुप्रा) के मामलों में फैसले याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील को आगे नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि वे ऐसे मामले हैं जहां हिरासत के आदेश को इस आधार पर निष्प्रभावी पाया गया कि सामग्री और महत्वपूर्ण तथ्यों को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाया गया था और पूर्वोक्त फैसले भी कानून का कोई प्रस्ताव नहीं देते हैं कि जहां जमानत दी गई है, निवारक हिरासत का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

31. इसके विपरीत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा हरधन साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (1975) 3 एससीसी 198 के मामले में दिए गए निर्णय में स्थापित कानूनी स्थिति यह है कि केवल इसलिए कि किसी बंदी पर आपराधिक अपराध करने के लिए आपराधिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है या उसे सीआरपीसी के अध्याय VIII में वर्णित अपराधों को करने से रोकने के लिए कार्यवाही की जा सकती है, सरकार को निरोध कानून के तहत

उसे हिरासत में लेने के लिए कार्रवाई करने से नहीं रोकता है। उपरोक्त निर्णय में यह भी दोहराया गया है कि यह तथ्य कि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर देती है और सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कदम उठाती है और यहां तक कि प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करती है, जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ निवारक निरोध कानून के तहत आदेश जारी करने पर कोई रोक नहीं लगा सकती है। उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:

“34. इस विषय पर इस न्यायालय के हाल के कई निर्णय हैं। बोरजहान मामले में लिए गए निर्णय गोरे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1972) 2 एससीसी 550, आशिम कुमार रे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1973) 4 एससीसी 76; अब्दुल अजीज बनाम जिला मजिस्ट्रेट, बर्दवान (1973) 1 एससीसी 301 और देबू महतो बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1974) 4 एससीसी 135 में निरोध आदेश वैध है या नहीं, इसके लिए पालन किए जाने वाले सिद्धांतों को सही ढंग से निर्धारित किया गया है। बिरम चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1974) 4 एससीसी 573 का निर्णय, जो दो विद्वान न्यायाधीशों की खंडपीठ का निर्णय है, तीन विद्वान न्यायाधीशों की प्रत्येक खंडपीठ के अन्य निर्णयों के विपरीत है। मोटे तौर पर ये सिद्धांत बताए जा सकते हैं। पहला, केवल इसलिए कि किसी बंदी पर आपराधिक अपराध करने के लिए आपराधिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है या दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय VIII में वर्णित अपराधों को करने से रोकने के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, अपने आप में सरकार को अधिनियम के तहत उसे हिरासत में लेने के लिए कार्रवाई करने से नहीं रोकेंगे। दूसरा, यह तथ्य कि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर देती है और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उस पर मुकदमा चलाने के लिए कदम उठाती है और यहां तक कि प्राथमिकी भी दर्ज करती है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निवारक निरोध के तहत आदेश जारी करने पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। तीसरा, जहाँ संबंधित व्यक्ति उस समय वास्तव में जेल में है जब उसके विरुद्ध निरोध का आदेश पारित किया जाता है और उसे उचित अवधि तक रिहा किए जाने की संभावना नहीं है, वहाँ यह तर्क दिया जा सकता है कि निरोध प्राधिकारी को इस बात की संतुष्टि नहीं हो सकती कि ऐसा व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो सकता है जो राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डाल सकती हैं। चौथा, केवल इस आधार पर कि अभियोजन के लंबित रहने के दौरान निरोध आदेश पारित किया जाता है, आदेश का उल्लंघन नहीं होगा। पाँचवाँ, निरोध का आदेश एक एहतियाती उपाय है। यह आसपास की परिस्थितियों के आलोक में किसी व्यक्ति के पिछले आचरण के आधार पर उसके भविष्य के व्यवहार के उचित पूर्वानुमान पर आधारित होता है।”

32. उपर्युक्त ऐतिहासिक न्यायिक घोषणा में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध और दंडात्मक निरोध के बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया है:

“32. निवारक निरोध की शक्ति दंडात्मक निरोध से गुणात्मक रूप से भिन्न है। निवारक निरोध की शक्ति एक एहतियाती शक्ति है जिसका प्रयोग उचित प्रत्याशा में किया जाता है। यह किसी अपराध से संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी। यह समानांतर कार्यवाही नहीं है। यह अभियोजन के साथ ओवरलैप नहीं करता है, भले ही यह कुछ तथ्यों पर निर्भर करता हो, जिसके लिए अभियोजन शुरू किया जा सकता है या शुरू किया जा चुका हो। अभियोजन से पहले या उसके दौरान निवारक निरोध का आदेश दिया जा सकता है। निवारक निरोध का आदेश अभियोजन के साथ या उसके

बिना और प्रत्याशा में या निर्वहन या यहां तक कि बरी होने के बाद किया जा सकता है। अभियोजन का लंबित होना निवारक निरोध के आदेश पर कोई रोक नहीं है।

33. अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता क्योंकि निवारक निरोध और अभियोजन समानार्थी नहीं हैं। उद्देश्य भिन्न हैं। प्राधिकारी भिन्न हैं। कार्यवाही की प्रकृति भिन्न है। अभियोजन में अभियुक्त को उसके पूर्व कृत्य के लिए दंडित करने का प्रयास किया जाता है। निवारक निरोध में, पूर्व कृत्य केवल बंदी के भविष्य के संभावित आचरण के बारे में अनुमान लगाने का आधार होता है।"

33. एक अन्य निर्णय में, पुलिस आयुक्त एवं अन्य बनाम सी. अनीता (श्रीमती) (2004) 7 एससीसी 467 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध के उद्देश्य और आशय को निम्नानुसार समझाया:

"5. निवारक निरोध एक पूर्वानुमानित उपाय है और किसी अपराध से संबंधित नहीं है, जबकि आपराधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित करने के लिए होती है। ये समानांतर कार्यवाही नहीं हैं। निवारक निरोध कानून का उद्देश्य दंडात्मक नहीं, बल्कि केवल निवारक है। इसका सहारा तब लिया जाता है जब कार्यपालिका को यह विश्वास हो जाता है कि निरुद्ध व्यक्ति को संबंधित कानून द्वारा निर्दिष्ट कुछ उद्देश्यों के प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए ऐसी निरोध आवश्यक है। किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने में कार्यपालिका की कार्रवाई केवल एहतियाती होने के कारण, सामान्यतः इस मामले को कार्यपालिका प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ देना आवश्यक होता है। आचरण के वस्तुनिष्ठ नियमों को विस्तृत रूप से निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है, जिनका पालन न करने पर निरोध हो जाए। इसलिए, निरोध करने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि को सर्वोपरि माना जाता है, और उसे अपने विवेक का प्रयोग करने की पूरी छूट है। निरोध करने वाला प्राधिकारी अपने समक्ष उपलब्ध किसी भी सामग्री और जानकारी के आधार पर कार्रवाई कर सकता है। ऐसी सामग्री और जानकारी केवल कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत संदेह का आधार प्रदान कर सकती है, लेकिन कानूनी प्रमाण के उन परीक्षणों को पूरा नहीं कर सकती जिन पर अकेले अपराध के लिए दोषसिद्धि मान्य होगी। समाज में व्यवस्था बनाए रखने की मौलिक आवश्यकता की बाध्यताएँ, जिसके बिना नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सहित सभी अधिकारों का आनंद अपने सभी अर्थ खो देगा, निवारक निरोध के कानूनों को औचित्य प्रदान करती हैं। निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले कानून यह मानते हैं कि किसी व्यक्ति का आचरण सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव, राज्य की सुरक्षा या वित्तीय आधार को नुकसान पहुँचाने वाला है, अपराधी की ओर से भविष्य में इसी तरह की प्रवृत्तियों के संभावित प्रकटीकरण के उचित पूर्वानुमान के लिए संतुष्टि का आधार प्रदान करता है। इस क्षेत्राधिकार को कभी-कभी संदेह का क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक समाज और सामाजिक व्यवस्था के स्वतंत्रता के मूल्यों के संरक्षण की बाध्यताएँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती को बाध्य कर सकती हैं। थॉमस जेफरसन ने कहा था, "लिखित कानून का ईमानदारी से पालन करके अपने देश को खोना, जीवन, स्वतंत्रता और उन सभी लोगों के साथ कानून को खोना होगा जो हमारे साथ आनंद ले रहे हैं, इस प्रकार बेतुके ढंग से आवश्यकताओं के लिए अंत का बलिदान करना होगा।" निस्संदेह, यही सैद्धांतिक क्षेत्राधिकार संबंधी औचित्य है। निवारक निरोध को सक्षम करने वाला कानून। लेकिन निवारक निरोध कानून के प्रशासन का वास्तविक तरीका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कानून को एक ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरी ओर एक व्यवस्थित समाज की आवश्यकताओं के बीच सही संतुलन बनाकर उचित ठहराया जाना चाहिए। भारत संघ बनाम अमृत मामले में इन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया था। लाल मनचंदा (2004) 3 एससीसी 75."

34. उपर्युक्त निर्णय याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए इस तर्क का भी उत्तर देते हैं कि एक बार Cr.PC की धारा 110 के तहत आदेश पारित होने के बाद, हिरासत कानून के तहत हिरासत का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। Cr.PC की धारा 110 आदतन अपराधियों से अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा लेने का प्रावधान करती है। इसके खंड (जी) में प्रावधान है कि जब किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में एक व्यक्ति है जो इतना हताश और खतरनाक है कि बिना सुरक्षा के उसका खुला रहना समुदाय के लिए खतरनाक है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट कानून के तहत प्रदान की गई रीति से ऐसे व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि उसे तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए, जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उसके अच्छे आचरण के लिए जमानतों के साथ एक बांड निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए। उपर्युक्त प्रावधान, सबसे पहले, केवल बांड निष्पादित करने की आवश्यकता रखता है और उस स्तर पर मजिस्ट्रेट को व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार नहीं देता है। हालांकि, निवारक निरोध की योजना विशेष कानून के तहत प्रदान की जाती है, यानी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम जो विशेष रूप से उन मामलों से निपटती है जहां कानून किसी व्यक्ति को स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल होने से रोकने के उद्देश्य से हिरासत में लेने की अनुमति देता है। 1988 का अधिनियम, अपने शुरुआती भाग में, दर्ज करता है कि स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक गंभीर खतरा है और ऐसे अवैध व्यापार में लगे व्यक्तियों की गतिविधियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इसलिए, उन व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए जिनके द्वारा और जिस तरीके से ऐसी गतिविधियों का आयोजन और संचालन किया जाता है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ क्षेत्रों में, जो स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं

इसलिए, यह स्पष्ट है कि 1988 के अधिनियम की योजना के तहत हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को दी गई हिरासत की शक्ति का उद्देश्य व्यक्तियों को मादक दवाओं और मनोवैज्ञानिक पदार्थों की अवैध तस्करी में शामिल होने से रोकना है। 1988 का अधिनियम विशेष कानून होने के नाते, उस अधिनियम के तहत दी गई हिरासत की शक्ति किसी भी तरह से, धारा 110 सीआरपीसी के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्यवाही और पारित आदेश द्वारा प्रतिबंधित या नियंत्रित नहीं है, जो एक सामान्य कानून है। इसलिए, 1988 के अधिनियम के प्रावधान, विशेष कानून होने के नाते, सामान्य कानून पर प्रबल होंगे। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क कि एक बार धारा 110 सीआरपीसी के तहत आदेश पारित होने के बाद, राज्य सरकार 1988 के अधिनियम की धारा 3 के तहत निवारक हिरासत का आदेश पारित करने की अपनी शक्ति से वंचित हो जाती है, कानून में अस्थिर होने के कारण खारिज कर दिया जाता है।

35. वर्तमान मामले में 1988 के अधिनियम की धारा 3 के तहत निरोधक प्राधिकारी द्वारा निवारक निरोध की शक्ति का आह्वान इस आधार पर किया गया है कि बंदी 1985 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों में बार-बार शामिल रहा है और उसके खिलाफ पांच साल की अवधि में आठ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2023 में एक से अधिक मामले बंदी द्वारा किए गए हैं, जो

1985 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों में लगातार शामिल रहे बंदी के बारे में एक राय बनाने का आधार प्रदान करता है और इसलिए, इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि बंदी को मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल होने से रोकने के लिए उसे निरोधित करना आवश्यक था। यह दंडात्मक निरोध का मामला नहीं है, बल्कि केवल निवारक निरोध का मामला है। निरोधक प्राधिकारी ने न केवल बंदी के खिलाफ आपराधिक मामलों के पंजीकरण को ध्यान में रखा है, आपराधिक मामलों में बंदी को जमानत देने के तथ्य को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है और यह ऐसा मामला नहीं है, जहां बंदी को जमानत दिए जाने के तथ्य से हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी अनभिज्ञ था। इसके अलावा, वर्तमान में ऐसा कोई मामला नहीं है, जहां बंदी ने दावा किया हो कि उसे 1985 के अधिनियम की धारा 37 के तहत सख्ती के बावजूद रिहा किया गया। बहस के दौरान कहा गया कि बंदी के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों में वाणिज्यिक मात्रा शामिल नहीं है और इसलिए, 1985 के अधिनियम की धारा 37 के तहत सख्ती लागू नहीं होती और यही कारण है कि बंदी को मादक दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी के अपराध में बार-बार शामिल होने के बावजूद आपराधिक अदालतों द्वारा समय-समय पर जमानत पर रिहा किया गया है। इसके अलावा, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 110 के तहत आदेश भी पारित किया गया था। ये वर्तमान मामले की विशिष्ट विशेषताएं हैं और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि तथ्यों के आधार पर, वर्तमान मामला ऐसा है जहां निर्णय लेने की प्रक्रिया और विवेक और संतुष्टि के प्रयोग को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक सामग्री और महत्वपूर्ण तथ्य हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाए गए थे ताकि यह कहा जा सके कि हिरासत का आदेश दोषपूर्ण है।

36. याचिकाकर्ता हिरासत के आदेश में किसी अन्य अवैधता की ओर इशारा नहीं कर सका, और न ही 1988 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन कर सका। सलाहकार बोर्ड की राय के अवलोकन से पता चलता है कि बंदी को सुनवाई का अवसर दिया गया था और उसके बाद, सलाहकार बोर्ड ने अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद यह राय बनाई कि बंदी को हिरासत में लेने का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद थे। हिरासत के आदेश और हिरासत के आधार, दोनों के बारे में बंदी को विधिवत सूचित किया गया था।

37. परिणामस्वरूप, इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

(आशुतोष कुमार), जे

(मनींद्र मोहन श्रीवास्तव), सीजे

मनोज नरवानी-आरजू/176

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी